दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, बुधवार 23 अक्टूबर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 27

महत्वपूर्ण एवं खास

इकबाल मिर्ची के खास गुर्गे हुमायूं मर्चेंट को प्रवर्तन निदेशालय ने किया गिरफ्तार

मुंबई (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय की मुंबई टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. ईडी ने अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची के खास गुर्गे हुमायूं मर्चेंट को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि इकबाल की अवैध संपत्ति, कारोबारी रिश्ते और राजनीतिक साठगांठ से जुड़े मामलों का लेखा जोखा हुमायूं ही रखता है. कांग्रेस सरकार के दौरान मंत्री रहे एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल से जुड़े संदिग्ध प्रॉपर्टी खरीद और बिक्री मामलों में भूमिका को लेकर हुमायूं का आरोपी बनाया गया है. ईडी के सूत्रों के अनुसार हुमायूं मुंबई के वर्ली लैंड डील मामले में प्रमुख तौर पर शामिल था. ईडी को यकीन है कि हुमायूं से पूछताछ के बाद इस मामले में अहम तथ्य सामने आ सकते हैं. जानकारों के अनुसार आने वाले समय में पूर्व मंत्री प्रफुल्ल पटेल की भी मुश्किलें बढ़ सकती है.

हम भी मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षमः राजनाथ

» पाक के परमाणु हमले की धमकी पर बोले रक्षामंत्री

नईदिल्ली (आरएनएस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि देश की समुद्री सीमाएं नौसेना के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है और उन्हें विश्वास है कि मुंबई जैसे आतंकवादी हमले की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। सेना भवन में यहाँ नौसेना के शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करने के बाद सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि कमांडरों से बातचीत के बाद वह आश्वस्त हैं कि समुद्री सीमाएं नौसेना के हाथों में सुरक्षित है। समुद्री सीमा पर चाक- चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है और उन्हें भरोसा है कि समुद्री सीमा के जरिये मुम्बई जैसे आतंकवादी हमले को दोहराया नहीं जा सकता। पाकिस्तान के मंत्री शेख रशीद के इस बयान पर कि अब तोप नहीं परमाणु बम चलेगा, उन्होंने कहा कि भारत कभी आक्रमक नहीं रहा है, ना किसी की एक इंच जमीन पर कब्जा किया लेकिन अगर किसी ने हमारी तरफ बुरी नजर से देखा तो हमारी सशस्त्र सेना किसी को भी मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है।

जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के सरकारी कामगारों को मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ

नईदिल्ली (आरएनएस)। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक संसद में पारित होने के उपरान्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अगस्त को राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया था, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर संघ क्षेत्र तथा लद्दाख संघ क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों को अन्य संघ क्षेत्रों के कर्मचारियों के बराबर सातवें वेतन आयोग की अंगीकृत सिफारिशों के अनुरूप सभी वित्तीय सुविधाएं दिये जाने का आश्वासन दिया था। इस आश्वासन के अनुरूप, गृहमंत्री अमित शाह ने 31 अक्टूबर से अस्तित्व में आने वाले जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघ क्षेत्रों के सभी सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अंगीकृत सभी भत्ते प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है और गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। भारत सरकार के इस निर्णय का लाभ 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जो कि अभी मौजूदा जम्मू कश्मीर राज्य में कार्यरत हैं और 31 अक्टूबर को इन दोनों संघ क्षेत्रों के कर्मचारी हो जायेंगे।

पेंशन के लिए नियमों में बदलाव करेगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार पेंशन से जुड़े केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत जल्द ही पेंशन पाने की उम्र सीमा बढ़ सकती है। यानि नियम बदलने पर कर्मचारियों को जहां पहले 58 साल की उम्र में पेंशन मिलने लगती थी वहीं अब 60 साल की उम्र में मिलेगी। सरकार ईपीएफ एक्ट में 1952 में बदलाव कर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र दो साल और बढ़ा सकती है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट की नवंबर में होने वाली दूसरी बैठक में इस बात पर विचार किया जा सकता है।

जापान सम्राट नारुहितो के राज्याभिषेक में कोविन्द ने की शिरकत

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दो देशों फिलीपींस और जापान के अपने दौरे के अंतिम चरण में सोमवार को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे।

राष्ट्रपति ने मंगलवार को जापान के शाही महल में सम्राट नारुहितो के राज्याभिषेक समारोह में शिरकत की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्याभिषेक समारोह के दौरान अलग से नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी से भेंट की। राष्ट्रपति ने विचार-विमर्श के दौरान कहा कि नेपाल के साथ निरंतर बढ़ती एवं मजबूत होती साझेदारी हमारी सरकार के लिए एक प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह पड़ोस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने संबंधी भारतीय विजन के अनुरूप है। राष्ट्रपति ने कहा, 'नेपाल के साथ अपनी विकास साझेदारी को भारत विशेष अहमियत देता है। नेपाल सरकार द्वारा तय की गई प्राथमिकताओं के अनुसार ही नेपाल के आर्थिक विकास एवं तरक्की में इस देश को आवश्यक सहयोग देने के लिए भारत प्रतिबद्ध है।'

फिर इसके बाद संध्या में, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जापान में भारत के राजदूत संजय कुमार वर्मा द्वारा टोक्यो में आयोजित स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा, 'भारत व्यापक बदलाव के पथ पर अग्रसर है। हमारी अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार के साथ विकसित हो रही है। हम नई बुनियादी ढांचागत सुविधाएं सृजित कर रहे हैं। हम डिजिटल अर्थव्यवस्था, नई प्रौद्योगिकियों, जलवायु परिवर्तन और ज्ञान समाज की रूपरेखा को विशेष स्वरूप प्रदान करने के मोर्चों पर पूरी दुनिया की अगुवाई करने के प्रयास कर रहे हैं। भारत अपनी प्रगति और समृद्धि में भाग लेने के लिए भारतीय समुदाय को अपार अवसर प्रदान करता है।' उन्होंने कहा, 'भारत दरअसल भारतीय समुदाय के सहयोग एवं प्रतिबद्धता की आशा रखता है, ताकि हमारे सपनों के भारत का निर्माण किया जा सके। यह एक ऐसा भारत होगा जो अपनी प्रगति एवं समृद्धि से लाखों घरों को रोशन करेगा। यही नहीं, यह एक ऐसा भारत होगा जो सभी की आवश्यकताओं का ख्याल रखेगा।'

राष्ट्रपति ने कहा, 'जापान के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध अत्यंत गहरे और ऐतिहासिक हैं। हम बौद्ध धर्म से लेकर हिंदू धर्म तक तथा उससे भी परे आध्यात्मिक एवं धार्मिक जुड़ाव को साझा करते हैं। हमारे रणनीतिक, राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग नए मुकाम पर पहुंच गए हैं। जापान हमारी अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव लाने में हमारे लिए एक प्रमुख साझेदार है। मुम्बई से अहमदाबाद तक हाई स्पीड रेल परियोजना में जापान की साझेदारी हमारे गहरे पारस्परिक विश्वास एवं मित्रता का एक प्रतीक है। पारस्परिक तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने भारत-जापान डिजिटल साझेदारी कायम की है।'

नोबेल पुरस्कार विजेता बनर्जी से मिले मोदी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी ने मंगलवार को मुलाकात की और दोनों ने विभिन्न मुद्दों पर 'गहन तथा अच्छी' चर्चा की। बनर्जी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हैं और उन्हें अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से दिया जाएगा। इन तीनों को वैश्विक स्तर पर गरीबी से लड़ने संबंधी शोध कार्यों के लिये 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। मोदी ने अपने आधिकारिक आवास में बनर्जी के साथ मुलाकात के बाद ट्वीट किया कि नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित अभिजीत बनर्जी के साथ शानदार मुलाकात। मानव सशक्तिकरण के प्रति उनका जुनून स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विभिन्न विषयों पर हमारे बीच अच्छी और गहन चर्चा हुई। भारत को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। मोदी ने बनर्जी के साथ अपनी मुलाकात की एक तस्वीर भी साझा की। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस महीने की शुरुआत में एक संवाददाता सम्मेलन में बनर्जी को बधाई देते हुए उन्हें 'वाम की ओर झुकाव वाला' बताया था। गोयल ने कहा था कि बनर्जी ने न्यूनतम आय योजना का सुझाव दिया था जिसे भारत की जनता ने नकार दिया था और 'उनकी सोच को स्वीकार करने' की आवश्यकता नहीं है।

अयोध्या मामलाः सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, समझौता या फैसला

नईदिल्ली (आरएनएस)। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में दूसरे दौर की मध्यस्थता से 70 साल पुराने विवाद का समाधान पेचीदा बन गया है। मामले में मुख्य पक्षकारों ने समाधान के बजाय फैसले पर जोर दिया है। सभी पक्षों में सहमति नहीं होने पर मध्यस्थता समिति सर्वसम्मति से समाधान नहीं कर सकता है।

दूसरे दौर की मध्यस्थता के समय को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है क्योंकि शीर्ष अदालत द्वारा 18 अक्टूबर को सुनवाई पूरी करने की समय-सीमा तय करने के बाद इसका प्रस्ताव किया गया।

मध्यस्थता करने के इस प्रस्ताव से सुन्नी वक्फ बोर्ड के दो गुटों में दरार पैदा हो गई है क्योंकि इसके वकील ने अदालत में मामले में सुनवाई पूरी करना पसंद किया और बोर्ड में समाधान चाहने वाले पक्षकारों का विरोध किया।

इस परिस्थिति में हिंदू पक्षकार विवादित स्थल को भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में स्थापित करने के लिए पहले ही काफी तर्क दे चुके हैं।

इसलिए माना जा रहा है कि हिंदू पक्षकार रणनीति के तहत अयोध्या विवाद में दूसरे दौर की मध्यस्थता से अलग हो गए हैं क्योंकि उनका मानना है कि बातचीत में शामिल पक्ष एक मंच पर नहीं आ सकते हैं।

हिंदू पक्ष के एक सूत्र ने कहा, हम देख सकते हैं कि वक्फ बोर्ड की राय में मतभेद है और मध्यस्थता का समर्थन करने वाले गुट को मामले में कई वर्षों से शामिल प्रमुख मुस्लिम पक्षकारों का समर्थन नहीं है। हमारा मानना है कि मध्यस्थता से समाधान के बजाय ज्यादा गड़बड़ी ही पैदा होगी। रामलला के वकीलों ने शीर्ष अदालत को साफतौर पर बता दिया कि उनको मध्यस्थता में हिस्सा लेने में दिलचस्पी नहीं है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के आदेश में रामलला, निर्मोही अखाड़ा और वक्फ बोर्ड के बीच 2.77 एकड़ विवादित भूमि को बराबर हिस्से में बांटने का फैसला हुआ था। रामलला और निर्मोही अखाड़ा में हमेशा टकराव बना रहा क्योंकि कोई विवादित स्थल को लेकर अपने दावे पर समझौता नहीं करना चाहते थे।

कर्नाटक से कांग्रेस नेता राममूर्ति ने थामा भाजपा का दामन

नई दिल्ली (आरएनएस)। कनार्टक से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य के एस राममूर्ति इस्तीफा देने के बाद मंगलवार भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में भाजपा महासचिव अरुण सिंह, भूपेन्द्र यादव और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी की मौजूदगी में राममूर्ति ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने बीते बुधवार को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।

राज्यसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों की संख्या अब 45 रह गई है, वहीं सदन में भाजपा सहित एनडीए के सदस्यों की संख्या 106 है, जबकि राज्यसभा में पांच सीटें अभी खाली है। उच्च सदन में अन्नाद्रमुक के 11, बीजद के सात, टीआरएस के छह, वाईएसआर कांग्रेस के दो सदस्यों का भी समर्थन भाजपा को प्राप्त होता है।

करतारपुर कॉरिडोर पर भारत-पाक के बीच करार टला

नई दिल्ली (आरएनएस)। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला समझौता फिलहाल टलता नजर आ रहा है। भारत और पाक दोनों ने बुधवार को समझौते पर हस्ताक्षर होने की घोषणा की थी, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि 23 अक्तूबर को दोनों देशों के बीच होने वाला समझौता टल गया है।

इससे पहले विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया था कि करतारपुर कॉरिडोर जाने वाले श्रद्धालुओं को पाकिस्तान द्वारा वीजा फ्री एक्सेस देने के लिए 23 अक्तूबर को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। 12 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर शुरू करने की योजना है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से एक बार फिर प्रति दर्शनार्थी 20 डॉलर (लगभग 1400 रुपये) का शुल्क हटाने की मांग की है। गौरतलब है कि भारत-पाकिस्तान अधिकारियों के बीच करतारपुर कॉरिडोर को लेकर तीन बैठकें हो चुकी हैं। अंतिम बैठक में पाकिस्तान ने प्रति श्रद्धालु 20 डॉलर फीस की शर्त रखी थी। भारतीय अधिकारियों ने इस शर्त का तुरंत विरोध किया था। भारत का तर्क था कि करतारपुर कॉरिडोर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए बनाया गया है।

'हुनर हाट' के जरिए रोजगार मुहैया कराएगी केंद्र सरकारः नकवी

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार हुनर हाट'के माध्यम से 'हुनर के उस्ताद' लाखों कारीगरों, शिल्पकारों, दस्तकारों और पारंपरिक खानसामों को रोजगार तथा रोजगार के मौके मुहैया कराएगी।

नकवी ने यह भी कहा कि अगला हुनर हाट प्रयागराज में आगामी एक से 10 नवम्बर के बीच आयोजित किया जायेगा। प्रयागराज में आयोजित किये जा रहे देश भर के हुनर के उस्तादों के मेले में बड़ी संख्या में महिला कारीगरों सहित देश के हर कोने से 300 से अधिक दस्तकार, शिल्पकार, खानसामे भाग लेंगे। 2019-2020 के सभी 'हुनर हाट', 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के थीम पर आधारित होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में देश के प्रसिद्ध आर्थिक केंद्रों में आयोजित एक दर्जन से ज्यादा 'हुनर हाट' के जरिये 2 लाख 50 हजार से ज्यादा कारीगरों, शिल्पकारों, दस्तकारों, खानसामों और उनसे जुड़े हुए लोगों को रोजगार और रोजगार के मौके मुहैया कराये गए हैं जिनमे बड़ी संख्या में महिला कारीगर भी शामिल हैं। उन्हेंने कहा कि अगले 5 वर्षों में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 100'हुनर हाट' का आयोजन करेगा। ये 'हुनर हाट' न दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, अहमदाबाद, देहरादून, पटना, इंदौर, भोपाल, नागपुर, रायपुर, हैदराबाद, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अमृतसर, जम्मू, शिमला, गोवा, कोच्चि, गुवाहाटी, रांची, भुवनेश्वर, अजमेर आदि में आयोजित किये जाएंगे। नकवी ने कहा कि 'हुनर हाट' में आने वाले दस्तकारों, शिल्पकारों का सशक्तिकरण तो हो ही रहा है साथ ही प्रत्येक दस्तकार, शिल्पकार के साथ कम से कम 40 से 50 लोग जुड़े होते हैं जिन्हें रोजगार के मौके मिलते हैं।

यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फिर फटकार

नई दिल्ली। यूपी के बुलंदशहर स्थित श्रीमंगला बेला भवानी मंदिर मामले में मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान अदालत ने यूपी सरकार से कहा कि ये अराजकता है। क्या उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक आदेश के तहत कुछ भी कर सकते हैं।

अदालत ने पूछा कि राज्य में मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून क्यों नहीं है? अदालत ने कहा कि यूपी सरकार इस संबंध में कानून बनाने पर विचार करे, जिसके तहत सरकार गलत प्रबंधन के आरोपों पर मंदिर व धार्मिक संस्था का मैनेजमेंट अपने अधिकार क्षेत्र में ले सके। अदालत ने सरकार से कहा कि मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के नियमन के लिए केंद्र सरकार का भी कानून है साथ ही कई राज्यों में भी कानून है। जब आपके राज्य में कानून नही है तो आपने केंद्र सरकार के कानून को नहीं अपनाया? अदालत ने यूपी सरकार को छह हफ्ते के अंदर यह सूचित करने के लिए कहा है कि वह कानून बना रहे हैं या नहीं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला केवल मंदिर का नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ा मसला है। हमें लोगों से मतलब है।

यूपी में है जंगलराज

इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा था कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से तंग आ चुके हैं। ऐसा लगता है यूपी

में जंगलराज है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि अधिकतर मामलों में यूपी सरकार की ओर से पेश वकीलों के पास संबंधित अथॉरिटी का कोई उचित निर्देश नहीं होता। बुलंदशहर के सैकड़ों वर्ष पुराने एक मंदिर से जुड़े प्रबंधन के मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने यह टिप्पणी की थी। जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल से पूछा गया था कि क्या यूपी में कोई ट्रस्ट या सहायतार्थ ट्रस्ट एक्ट है? क्या वहां मंदिर व सहायतार्थ चंदे को लेकर कोई कानून है?

केंद्र ने कर्मचारियों के लिए दी तोहफा नीति में छूट

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए तोहफे स्वीकार करने की वित्तीय सीमाओं को बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि तीन गुणा बढ़ोतरी कर इस सीमा में छूट दी गई है। उन्होंने हाल में संशोधित किए गए नियमों का हवाला देते हुए बताया कि समूह 'अ' और 'ब' श्रेणियों के तहत आने वाले अधिकारियों को 5,000 रुपये से अधिक का तोहफा सरकार की मंजूरी के बिना नहीं स्वीकार करना चाहिए। इससे पहले कर्मचारियों के इन समूहों के लिए तोहफा स्वीकार करने की सीमा 1,500 रुपये थी। इसी तरह समूह 'स' के कर्मचारी सरकार की मंजूरी लिए बिना अब 500 रुपये की बजाए 2,000 रुपये तक की भेंट स्वीकार कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि सीमा में यह संशोधन तीन अखिल भारतीय

जमानत मिलने के बाद भी जेल में रहेंगे चिदंबरम

» आईएनएक्स मीडिया मामला

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को मंगलवार को जमानत दे दी। सीबीआई की ओर से दर्ज इस मामले में गिरफ्तार किए जाने के दो महीने बाद चिदंबरम को यह राहत मिली है लेकिन उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने एक अन्य मामले में पहले ही उन्हें गिरफ्तार किया है।

न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने चिदंबरम को जमानत प्रदान करते हुये दिल्ली उच्च न्यायालय का 30 सितंबर का फैसला निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के इस मामले में चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विशेष अदालत में एक लाख रूपए का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानती देने पर चिदंबरम को रिहा कर दिया जाये। न्यायालय ने सीबीआई की इस दलील को दरकिनार कर दिया कि 74 वर्षीय चिदंबरम ने इस मामले में दो प्रमुख गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया था। पीठ ने कहा कि जांच ब्यूरो के अनुसार चिदंबरम ने गवाहों को प्रभावित किया और आगे भी प्रभावित किये जाने की संभावना पूर्व वित्त मंत्री को जमानत से इंकार करने का आधार नहीं हो सकता जबकि निचली अदालत में उनकी हिरासत के लिये दाखिल छह आवेदनों में कहीं भी इस तरह की सुगबुगाहट तक नहीं है।